



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003/चैत्र 22, 1925

No. 51]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003/CHAITRA 22, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/56/2002-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण वर्ष 2002-03 के लिए तेल जेट्टी सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कार्गो के लिए तदर्थ घाटशुल्क दर निर्धारित करने हेतु न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/56/2002-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास

आवेदक

आदेश

(मार्च, 2003 के 28वें दिन पारित)

यह मामला मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए समर्पित जेट्टी सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कार्गो के लिए वर्ष 2002-03 हेतु तदर्थ घाटशुल्क दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए वर्ष 2002-03 हेतु एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ घाटशुल्क दरें निम्नलिखित हैं :-

- (i) 15 मई, 2002 तक जेट्टी सं. 10 के लिए 148.49 रुपए ; और, 16 मई, 2002 से 31 मार्च, 2003 के लिए 144.70 रुपए।
- (ii) 16 मई, 2002 से 31 मार्च, 2002 तक जेट्टी सं. 11 के लिए 80.67 रुपए प्रति मी.ट.।

2.1 एनएमपीटी से प्राप्त यह प्रस्ताव एमआरपीएल को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। एमआरपीएल ने घाटशुल्क दर के परिकलन के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य आपत्तियाँ उठायीं हैं :-

- (i) एनएमपीटी द्वारा लिए गए यातायात आँकड़े वास्तविक नहीं हैं। यातायात अनुमान, बजट अनुमानों के स्थान पर वास्तविक आँकड़ों पर आधारित होने चाहिए।

- (ii) अधिशेष बकाया राशियों पर ब्याज लागत एनएमपीटी द्वारा अनुमानित 20.50 करोड़ रुपए के स्थान पर केवल 14 करोड़ रुपए बनती है।
- (iii) निकर्षण लागत पर विचार बजट अनुमानों के स्थान पर भारतीय निकर्षण निगम (डीसीआई) के साथ हुए करार के आधार पर होना चाहिए।
- (iv) ऋण वापसी राशि से मूल्यहास महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निर्देशानुसार कम किया जाना चाहिए।
- (v) एनएमपीटी ने जेट्टी सं. 11 के एस्क्रो खाता शेष पर ब्याज आय को नहीं लिया है।
- (vi) इसने निवेश पर प्रतिलाभ को घाटशुल्क के परिकलन में लेने की अनुमति नहीं देने संबंधी अपने पूर्व मत को दोहराया है।

2.2 उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए, एमआरपीएल ने वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 हेतु 37.56 रुपए प्रति मी.ट. और जेट्टी सं. 11 हेतु 20.42 रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दरों का सुझाव दिया है।

3.1 यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एमआरपीएल ने इस प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई, 2000 को पारित आदेश के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसने मुख्य रूप से एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों पर किए गए निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) को अनुमति देने संबंधी मुद्दे को चुनौती दी है।

3.2 एनएमपीटी ने भी तीन मुख्य मुद्दों अर्थात् जलयान संबंधी आय की जमा वापसी, एस्क्रो खाता ब्याज की जमा वापसी और घाटशुल्क का परिकलन करते समय मूल्यहास की अधिकता से ऋण वापसी पर विचार करने के लिए एनएमपीटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर 21 मार्च, 2002 को पारित इस प्राधिकरण के आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

4. इस मामले की संयुक्त सुनवाई 20 मार्च, 2003 को हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, घाटशुल्क दर के परिकलन संबंधी विवादों के बावजूद, एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों लागत व्यौरों पर विचार किए बिना और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में अपने अधिकारों और दावों की तरफदारी किए बिना वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 दोनों के लिए 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दर के लिए सहमत हैं।

5. हालांकि वहाँ बहुत से तर्क दिए गए थे, विशेष रूप से विभिन्न लागत तत्वों और यातायात अनुमान की उपयुक्तता और स्वीकार्यता के संबंध में, परंतु एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों 20 मार्च, 2003 को हुई संयुक्त सुनवाई में लागत व्यौरों पर विचार किए बिना वर्ष 2002-03 के लिए वसूली करने हेतु तदर्थ रूप में प्रभारों की व्यवस्था करने पर सहमत हो गए थे। दोनों पक्षों ने वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 दोनों हेतु 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ घाटशुल्क दर को स्वीकार करने की अपनी इच्छा दर्शाते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार प्रस्तुत किया है। चूंकि पारस्परिक सहमति दर इस तथ्य की पुष्टि और मान्यता प्रदान करता है कि ऐसी दर केवल अंतिम दरों का निर्धारण होने तक अंतरिम दर के रूप में कार्य करती रहेगी, लागत सिद्धांतों और आँकड़ों पर दोनों पक्षों द्वारा शुरू में उठाई गई विभिन्न आपत्तियों का गहराई से विश्लेषण करने एवं उपयुक्तता और पहले से निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उसकी पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लागत तत्वों की आगे जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह प्राधिकरण एनएमपीटी और एमआरपीएल के बीच हुई परस्पर सहमति के अनुसार वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ दर अनुमोदित करता है।

6. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से यह प्राधिकरण वास्तविक और स्वीकार्य लागतों के आधार पर अंतिम घाटशुल्क प्रभारों का निर्धारण होने तक एनएमपीटी में जेट्टी सं. 10 और 11 के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान प्रहस्तित कार्गो पर 71/- रुपए प्रति मी.ट. की तदर्थ घाटशुल्क दर अनुमोदित करता है।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th April, 2003

No. TAMP/56/2002-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the New Mangalore Port Trust for fixation of ad-hoc wharfage rate for the cargo handled at oil Jetties No. 10 and 11 for the year 2002-2003 as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**Case No. TAMP/56/2002-NMPT**

The New Mangalore Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 28th day of March 2003)

This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of an ad-hoc wharfage rate for the year 2002-03 for the cargo handled at Jetties No. 10 and 11 dedicated for the Mangalore Refinery and Petrochemical Limited (MRPL). Ad-hoc wharfage rates proposed by the NMPT for the year 2002-03 for Jetties No. 10 and 11 are as follows:

- (i). Rs. 148.49 for Jetty No.10 upto 15 May 2002; and, Rs. 144.70 from 16 May 2002 to 31 March 2003.
- (ii). Rs. 80.67 PMT for Jetty No. 11 from 16 May 2002 to 31 March 2003.

2.1. The proposal received from the NMPT was forwarded to the MRPL for their comments. The MRPL has raised the following main objections with reference to the computation of the wharfage rate:

- (i). The traffic figures adopted by NMPT are not realistic. The traffic projections should be based on actuals instead of Budget Estimates.
- (ii). The interest cost on outstanding balances works out to only Rs. 14 crores as against Rs. 20.50 crores considered by the NMPT.
- (iii). The dredging cost should be considered based on the agreement with the Dredging Corporation of India (DCI) instead of Budget Estimates.

- (iv). Depreciation should be reduced from the loan repayment amount in accordance with the direction of the TAMP.
- (v). The interest income on Escrow account balance on Jetty No. 11 has not been considered by the NMPT.
- (vi). It has reiterated its earlier view about not allowing return on investment in calculation of wharfage rate.

2.2. Taking into consideration the above points, the MRPL have suggested ad hoc rates of Rs. 37.56 PMT for Jetty No. 10 and Rs. 20.42 PMT for Jetty No. 11 for the year 2002-03.

3.1. It may be relevant to mention that the MRPL has filed a Writ Petition in the High Court of Karnataka against the Order passed by this Authority on 19 July 2000. It has mainly challenged the issue relating to allowing Return on Investment (ROI) on the NMPT assets.

3.2. The NMPT has also filed Writ Petitions in the High Court of Karnataka for a review of the Authority's Orders passed on 21 March 2002 rejecting the review petitions filed by the NMPT on three specific issues viz. credit back of vessel related income, credit back of escrow account interest and consideration of repayment of loan in excess of depreciation while computing the wharfage rate.

4. A joint hearing in this case was held on 20 March 2003. At the joint hearing, notwithstanding the disputes about computation of the wharfage rate, both the NMPT and the MRPL agreed for an adhoc rate of Rs.71/- PMT for both the Jetties No.10 and 11 for the year 2002-03 without going into the cost details and without prejudice to their rights and contentions in the Writ Petitions pending before the High Court of Karnataka.

5. Although there were lot of arguments, particularly in respect of reasonableness and admissibility of different cost elements and the traffic projection, both the NMPT and the MRPL have come to an agreement insofar as the ad-hoc charges leviable for the year 2002-03 at the joint hearing held on 20 March 2003 without going into the cost details. Both the parties have submitted a written agreement jointly signed by them indicating their willingness to accept an adhoc wharfage rate of Rs. 71/- PMT for both the Jetties No. 10 and 11 for the year 2002-03. Since a mutually agreed rate has evolved and recognizing the fact that such a rate is only going to serve as an interim rate subject to fixation of final rates, it may not be necessary to analyse in depth the various objections raised initially by both the parties on costing principles and figures as well as further scrutiny of various cost elements to ensure the

reasonableness and their conformity with the guidelines already set. This Authority is, therefore, inclined to approve the ad-hoc rate of Rs.71/-PMT for Jetties No. 10 and 11 for the year 2002-2003 as mutually agreed to between the NMPT and the MRPL.

6. In the result, and for the reasons given above, this Authority approves an ad-hoc wharfage rate of Rs.71/- PMT on cargo handled during the year 2002-03 for Jetties No. 10 and 11 at the NMPT subject to determination of final wharfage charges based on actual and admissible costs.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2003/Exty.]